लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16- 31 दिसंबर 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -56

"किताबों का अध्ययन न केवल शब्दों की संपदा को बढ़ाता है, दिमाग की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है।

: एंटोनियो

श्रीमद्भागवत गीता आध्यात्मिक दीप स्तंभः राष्ट्रपति

3

जितेन्द्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड

6

आजादी के अमृत महोत्सव में दास्तान-ए-अंबाला

8

सबकी सलाह पर तैयार होगा सबका बजट

मनोज प्रभाकर

विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निर्बाध गति से चलती रही और आम जनमानस की जरूरतें बराबर पूरी होती रहें, इसके लिए जरूरी है पर्याप्त रोकड़ा। पर्याप्त रोकड़ा वित्त प्रबंधन का अलंकार है। प्रदेश के वित्त प्रबंधन का कामकाज देख रहे स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी कोना विकास से अछूता ना रहे। हर परिवार को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ मिले तथा बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का समान विकास हो। राज्य सरकार इसी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ते हुए वित्त प्रबंधन से संबंधित नई परंपरा को आगे बढ़ा रही है। नई पहल है 'सबकी सलाह पर सबका बजट।'

आगामी दिनों में होने वाले विकास कार्यों के लिए वित्त प्रबंधन की रूपरेखा बनाई जा रही है। अनुमान है कि वर्ष 2023-24 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण आदि क्षेत्रों पर मुख्य फोकस रहेगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए संबंधित हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है।

हरियाणा विधानसभा द्वारा अयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आय और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद उसमें बदलाव करना संभव नहीं होता है। प्रायः देखा जाता है कि जब बजट पेश किया जाता है, उस समय विधायक अपने -अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों की मांग रखते हैं, लेकिन उस समय उन मांगों को बजट में शामिल करना संभव नहीं होता। बजट में अभी तीन महीने का समय है, इसलिए इन तीन माह के दौरान सभी विधायक अपने -अपने क्षेत्रों में करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची वित्त विभाग या संबंधित मंत्री या सीधे उन तक भेज सकते हैं, ताकि उन मांगों को बजट मसौदे में शामिल किया जा सके।

राज्य सरकार ने बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से प्री-बजट परामर्श बैठकें शुरू की हैं। वर्ष 2020-21 का पहला बजट प्रस्तुत करने से पहले किसानों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों सांसदों, विधायकों आदि से बजट पूर्व चर्चा की गई थी और उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया था। इस साल के बजट से पूर्व भी आठ बैठकें कर 477 हितधारकों से चर्चा की गई हैं। ये बैठकें सभी विभागों के अधिकारियों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, उद्योग व वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्विस सेक्टर और रियल स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ की गईं। इतना ही नहीं, इस बार बजट पर विचार विमर्श के लिए विधायकों की आठ समितियां भी बनाईं जिनमें 74 विधायक शामिल हुए। प्रस्तावित बजट के लिए सुझाव भी मिले। इनमें से व्यावहारिक सुझावों पर अमल करते हुए संतुलित बजट तैयार किया जा रहा है।

केंद्रीय बजट में विशेष पैकेज देने की मांग

हरियाणा के 14 जिलें ऐसे हैं जो एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण और रख-रखाव के लिए काफ़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में एनसीआर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की।

हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 164.3 लाख जनसंख्या एनसीआर के अंदर आती है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे, पानी, स्वच्छता, शहरी विकास और कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। एनसीआर में हरियाणा सरकार केएमपी एक्सप्रेस-वे, रेल आर्बिटल प्रोजेक्ट, पंचग्राम विजन के रूप में केएमपी कॉरिडोर के साथ 2.5 लाख हैक्टेयर के 5 शहरों का विकास, नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार व अन्य बड़ी परियोजनाओं पर पैसे खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए हरियाणा सरकार की केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग जायज है। राज्य को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में इस योजना के तहत 874 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। सीएम ने केंद्र सरकार से इस योजना को भविष्य में भी जारी रखे जाने का भी अनुरोध किया।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

'चिरायु हरियाणा' योजना का शुभारम्भ

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ़्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में चिरायु योजना का शुभारम्भ हो गया है। एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय तक के करीब 28 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान भारत योजना से संबंधित दस लाख लाभार्थियों को वर्चुअली रूप से चिरायु कार्ड वितरण की शुरूआत की। ये कार्ड प्रदेश के 1600 गांवों व शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित शिविरों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि एक महीने से भी कम समय में 1888 लोग पहले ही योजना का लाभ ले चुके हैं।

प्रदेश में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने की शुरुआत की है। इस योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को पांच लाख रुपए तक के इलाज खर्च की चिंता नहीं रहेगी।

आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इस लिहाज़ से देखा जाए तो हरियाणा के 22 जिलों में हर जिले में लगभग 32 अस्पतालों में इस योजना से जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। 1500 तरह की बीमारियों का इलाज इस योजना के जरिए संभव हो सकेगा।

गुरुग्राम के 500 एकड़ में बनेगा जैव विविधता पार्क व झील

गुरुग्राम जिला के गांव दमदमा, खेड़ला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण होगा तथा लगभग 80 एकड़ में दमदमा झील का पुनः निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की। यह परियोजना गुरूजल, हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट तथा ई वाई फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी।

राज्य सरकार इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। सीएम ने कहा कि जैव विविधता के नाते हमारे साथ रहने वाले जीव जंतुओं की चिंता जरूरी है, क्योंकि यह पृथ्वी और प्रकृति केवल मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु सभी जीव जंतुओं के लिए है।

मुख्यमंत्री ने ई वाई फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि यह कंपनी इस प्रोजेक्ट पर

स्वेच्छा से 70 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनियों को अपना सीएसआर फंड सही ढंग से सामाजिक कार्यों में खर्च करने को प्रेरित करने के लिए हमने हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट बनाया है। पिछले एक वर्ष में कंपनियों ने इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रदेश में 542 करोड़ रुपए सीएसआर के खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कंपनियों का आह्वान करेंगे कि प्रदेश में कम से कम एक हजार करोड़ रुपए सीएसआर के माध्यम से सामाजिक कार्यों में लगें। इस पैसे को पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।

जैव विविधता पार्क और झील के विकास के अलावा, गुरुग्राम तथा नूंह जिलों में अरावली की पहाड़ियों में लगभग 10 हजार एकड़ में जंगल सफारी बनाने का कार्य भी प्रस्तावित है। इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

चार चरणों में विकसित होगा पार्कः परियोजना चार चरणों में विकसित होगी। पहले चरण में क्षेत्र के पेड़-पौधों व मिट्टी आदि का अध्ययन करने के साथ नर्सरी का निर्माण व झील की सफाई की जाएगी। दूसरे चरण में वॉटर शैड मैनेजमेंट व पौधारोपण की शुरूआत होगी, तीसरे चरण में झील का विकास और चौथे चरण में पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दमदमा झील का जीर्णोद्धार चार साल में और जैव विविधिता पार्क विकसित करने का कार्य 10 साल में पूरा होगा।

सभी को मिलकर करनी होगी पानी की बचत

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी की बचत करने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें उपलब्ध पानी का प्रबंधन करके इसका सदुपयोग करना होगा, अन्यथा भावी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है और भविष्य में पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। इसलिए सभी को जागरूक होकर पानी की बचत और संचयन में अपनी भागीदारी करनी होगी। पानी बचाने व ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए सभी एकजुटता से काम करें। शोधित पानी को खेती, सिंचाई आदि कार्यों में उपयोग किया जाए। नई कॉलोनियों में पानी की डबल पाइप लाइन डाली जा रही है, जिसमें पीने का स्वच्छ पानी एक लाइन में आएगा और दूसरी में शोधित पानी की आपूर्ति होगी। उद्योगों में भी शोधित पानी की आपूर्ति की जाएगी।

संपादकीय

आठ साल, राख्या ख्याल

गत आठ वर्षों में हरियाणा की सरकार ने वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास के नए मानक तय किए हैं। प्रदेश नेतृत्व के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी इसी विकास यात्रा का अभिनंदन है। प्रधानमंत्री ने इसे सर्वाधिक ईमानदार सरकार बताया है।

वस्तुतः इन आठ सालों में कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए गए। विकास का पहिया चारों ओर घूमा है, इसीलिए तो हरियाणा की मनोहर लाल सरकार का ध्येय है कि हरियाणा के हर परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1.80 लाख रुपए हो। हरियाणा की लोकप्रिय मनोहर सरकार द्वारा आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ाए गए कदमों का ही असर है कि महज लगभग डेढ़ साल पहले यानी अप्रैल, 2021 में शुरू की गई 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के तहत सबसे गरीब 33 हजार लोगों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण कार्यों का ही प्रतिफल है कि जीवन के हर क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन का असर दिख रहा है। बिना किसी भेदभाव के सरकार के कामों में जहां अभूतपूर्व पारदर्शिता आ गई है, वहीं सम्मान से जीने के हक के साथ हरियाणवी खुद पर गर्व महसूस कर रहा है।

अन्य उपलब्धियां जो ध्यान खींचती हैं-

» पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।
» विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की पेंशन 2500 रुपए प्रतिमाह
» पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित।
» हिसार में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित।
» प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना में खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की आयु होने पर तीन हजार रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन।
» सोनीपत-जींद रेलवे स्टेशन पर यातायात शुरू।
» हिसार में बना प्रदेश का पहला एयरपोर्ट।
» अम्बाला और भिवानी में रिंग रोड तथा हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पिंजौर तथा जींद नगरों में बाईपास बनाए गए।
» मेयर अथवा अध्यक्ष का सीधे ही जनता द्वारा चुनाव।
» राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधा पंचायतीराज संस्थाओं के खातों में दिया जा रहा है।

लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद विकास की यात्रा अपनी निरंतरता बनाए हुए है।

और अभी हाल ही में गुरुग्राम में 500 एकड़ में जैव-विविधता पार्क बनाने की घोषणा इसी क्रम की एक विशिष्ट उपलब्धि है।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

मंडल स्तर पर शुरू होगा 'जीएसटी आमने-सामने' कार्यक्रम

प्रदेश में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसके आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल को सिफ़ारिश की जा चुकी है। इनके अलावा जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हिसार व गुरुग्राम में 2 जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जायेंगे।

गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित किए गए एक दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए करदाताओं, अधिवक्ताओं व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को साझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर 'जीएसटी आमने-सामने' शुरू किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि एक साल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तीन अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन व हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश के सभी टैक्स अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वॉलं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाने में सहयोग करें।

टैक्स अधिवक्त ाओं के लिए लाइब्रेरी

मुख्यमंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान के रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला में टैक्स संबंधी विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी डीआईटीसी कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के बैठने के लिए वहीं पर कैंटीन की सुविधा वाले प्रतीक्षा हॉल भी बनाया जाएंगा, जहां टैक्स संबंधी सुनवाई के लिए कार्यालय में आने वाले टैक्स अधिवक्ता अपने करदाताओं के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर सकेंगे।

कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत

कर संग्रहण में हरियाणा प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा में देश की आबादी का केवल 2 प्रतिशत है वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो देश में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.6 प्रतिशत है, लेकिन देश के कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय टैक्स अधिवक्ताओं तथा करदाताओं को देते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश में करदाताओं का विश्वास जीतना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसमें टैक्स अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वैट से जुड़े विषयों की पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं कि साल दर साल के क्रम में इसकी पेंडसी को कम किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट की प्रक्रिया के तहत सबसे पुरानी डेट की पेंडसी को पहले क्लियर किया जाएगा।

आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि देश मे जीएसटी कानून को लागू करना एक बहुत ही कठिन निर्णय था। उन्होंने कहा कि जितने भी देशों ने अभी तक जीएसटी लगाया है, उसका क्रियान्वयन एक जटिल प्रक्रिया रही है। उन्होंने आस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया आदि देशों का जिक्र करते हुए कहा कि इन देशों में आम जनमानस के बीच जीएसटी को लेकर एक असंतोष भी था लेकिन भारत ही ऐसा एकमात्र देश है, जहां बिना किसी रुकावट व आमजन के असंतोष के इस कानून को सफलतापूर्वक लागू किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने, टैक्स चोरी को रोकने व लोग समय से अपनी सही रिटर्न्स भरें, इसकी जिम्मेदारी टैक्स अधिवक्ताओं व उनके विभाग पर है।

-संवाद ब्यूरो

युवाओं को प्रशिक्षण देगा टेक महिंद्रा फाउंडेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए मनोहर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्वावलंबी युवा-आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने और प्रदेश में पॉलिटेक्निक छात्रों के समग्र विकास के लिए एचएसबीटीई ने टेक महिंद्रा फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता ज्ञापन पर एचएसबीटीई के सचिव डॉ. राजेश गोयल और टेक महिंद्रा फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साजिद अली द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन के अनुसार टेक महिंद्रा फाउंडेशन चार चिन्हित क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इनमें मासिक धर्म स्वच्छता पर किशोर लड़कियों को प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा एवं सीपीआर से संबंधित युवाओं को प्रशिक्षण, फैसिलिटेशन स्किल्स एवं क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज पर शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा उद्यमिता कौशल पर छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना शामिल है।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

दस साल पुराने आधार के पते दोबारा सत्यापित कराना अनिवार्य

जिन नागरिकों के आधार कार्ड 10 साल से अधिक समय पहले बनाए गए थे, उन्हें पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करके अपने आधार विवरणों को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है, ताकि वे सरकारी सेवाओं का लाभ सुनिश्चित कर सकें।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अतिरिक्त उपायुक्तों को प्रदेश में आधार अपडेशन के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने स्टेट रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक मिनी सचिवालय में कम से कम 3 ऑपरेशनल किट और सभी जिलों में एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, उप-तहसीलों और ब्लॉकों में कम से कम एक ऑपरेशनल किट अवश्य रखें।

आईटी विभाग के अधिकारियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन-हाउस मॉडल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधार इको सिस्टम को मज़बूत करने के लिए केवल चयनित आधार केंद्रों पर नागरिकों के नए नामांकन की सुविधा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है और ऐसे केंद्रों की सूची स्टेट रजिस्ट्रार, एग्जिक्यूशन मैनेजमेंट ऑफ स्टेट पोर्टल फॉर न्यू एनरोलमेंट द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के लंबित मामलों को दूर करने के लिए आईटी विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से कैंपों का आयोजन करें। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी नवजात शिशु आधार के नए नामांकन के तहत कवर हों।

स्कूल शिक्षा विभाग को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में ऐसे बच्चों, जिनका आधार नहीं बना है, उनके नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए नियमित शिविर लगाने के लिए एक रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, आंगनवाड़ियों में भी ऐसे शेष बच्चों के नामांकन के लिए भी नियमित तौर पर कैंप लगाने के लिए कहा गया है।

हरियाणा की आधार कार्ड स्थिति को प्रस्तुत करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ की उप महानिदेशक भावना गर्ग ने अवगत कराया कि मार्च, 2023 तक 13.20 लाख आधार कार्ड अपडेट करने का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक राज्य में 299,57,178 आधार कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 5 वर्ष तक की जनसंख्या के 18,01,041 आधार कार्ड, 5 से 8 वर्ष की आयु के 67,12,666 आधार कार्ड और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 2,14,43,470 आधार कार्ड शामिल हैं। इस प्रकार, राज्य में 100.37 प्रतिशत आधार कार्ड बन चुके हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।

भीमराव अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृत्ति योजना-2022-23 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य समुदाय के छात्रों से 1 से 31 जनवरी 2023 तक saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव

श्रीमद्भागवत गीता आध्यात्मिक दीप स्तंभः राष्ट्रपति

विशेष प्रतिनिधि

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ करते हुए हरियाणा सरकार के विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ किया और भगवान श्रीकृष्ण का धन्यवाद किया कि हरियाणा में बतौर राष्ट्रपति उनकी पहली यात्रा का आरंभ धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस पावन गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पावन भूमि है। इसी सरस्वती के तट पर वेद और पुराणों को लिपिबद्ध किया गया। महाभारत में कुरुक्षेत्र के इस क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक ने भी पवित्र ग्रंथ गीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। यह बड़े हर्ष का विषय है कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने वर्ष 2016 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया। इस वर्ष महोत्सव में पार्टनर देश नेपाल और पार्टनर राज्य मध्यप्रदेश हैं। उन्हें बड़ी खुशी है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इस भव्य आयोजन में पहुंचे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहां के जवानों, किसानों व बेटियों ने अपने जीवन में गीता के कर्म करने के संदेश को अपनाया है। इससे जवानों ने देश की सेना में, किसानों ने अन्न पैदा करके और महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहराकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। हमें इन सभी पर गर्व है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि श्रीमद्भगवदगीता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक है, विश्वभर में अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जितनी टिकाएं श्रीमद्भगवद्गीता पर लिखी गई हैं, शायद ही किसी पुस्तक पर लिखी गई होंगी। श्रीमद्भागवत गीता आध्यात्मिक दीप स्तंभ है।

गीता में है धर्म और अध्यात्म का सारः राज्यपाल

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि गीता में धर्म और अध्यात्म का सार है। सही मार्गदर्शन किया जाए तो गीता विश्व को आतंकवाद जैसी बीमारी का भी समाधान दे सकती है। उन्होंने कहा कि विश्व में द्वंद एवं अराजकता फैल जाती है तो गीता से ही शांति लाई जा सकती है। इससे मनुष्य को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। गीता में विश्व की सभी संस्कृतियों का जीवन है। इसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना है। विश्वव्यापी 75 भाषाओं में गीता का प्रकाशन हुआ है और इसकी स्वीकृति को प्रमाणिक किया गया है। उन्होंने कहा कि गीता के समान ऊंचा प्रेरणा परक कोई ग्रंथ नही है। गीता प्रेरणा देती है और असहाय जीवन में जान फूंकती है। यह किसी मजहब का नही मानव जीवन का सारांश है।

राष्ट्रपति की उपस्थिति से उत्साह हुआ दोगुना -मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने पर हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि कर्मयोग की भूमि धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र में गीता जयंती की बेला पर राष्ट्रपति का हरियाणा में प्रथम आगमन अत्यंत शुभकारी है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों से गीता जयंती महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में मनाया जा रहा है, इस आयोजन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति से उत्साह दोगुना हो गया है।

तीन बड़ी परियोजनाओं की सौग़ात

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्रीमद्भगवद्गीता की पावन धरा धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रमों के दौरान प्रदेश को तीन बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की।

निरोगी हरियाणा योजना

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अंत्योदय परिवारों के लिए निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच मुफ्त की जाएगी। पहले चरण में 1 लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जाएगा, जबकि शेष आबादी को बाद के चरणों में कवर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा करते हुए यह विज़न पेश किया था कि प्रदेश के सभी नागरिकों की 2 साल में कम से कम एक बार व्यापक स्वास्थ्य जांच मुफ्त की जाए। इसी घोषणा को मूर्तरूप देते हुए निरोगी हरियाणा योजना बनाई गई है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा जारी अंत्योदय परिवारों के आंकड़ों के अनुसार कुल घरों की संख्या 26,64,257 है और जनसंख्या 1,06,06,475 है।

रोडवेज में ई-टिकटिंग प्रणाली

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रदेशवासियों को निर्बाध और सुगम परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रणाली का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रपति को पहली टिकट के रूप में नेशनल ई-मोबिलिटी कार्ड की प्रतिकृति भेंट की गई।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रारंभिक चरण में 6 डिपो अर्थात् चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में ई - टिकटिंग प्रणाली लागू होगी। इसी तरह हरियाणा रोडवेज के शेष 18 डिपो में जनवरी 2023 के अंत तक इस परियोजना को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा ।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य राजस्व लीकेज को बंद करना है। साथ ही ओपन लूप टिकटिंग के उपयोग को बढ़ावा देना, जिसे बाद में पूरे भारत में यात्रा के अन्य तरीकों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, छूट पाने वालों की पहचान, फर्जी पास को खत्म करना, रियायत पाने वाले यात्रियों के लिए कागजी बचत, कॉमन मोबिलिटी कार्ड के उपयोग के माध्यम से यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना, यात्रियों की संख्या के अनुरूप रूट राशनलाइजेशन तथा बसों, सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।

सिरसा को मेडिकल कॉलेज

हरियाणा सरकार नागरिकों को प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डाक्टरों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए और वांछित डाक्टर रोगी अनुपात प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति ने जिला सिरसा में 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस पर लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाविद्यालय की स्थापना से जिला सिरसा व आस-पास के क्षेत्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस महाविद्यालय में 100 एमबीबीएस छात्रों का वार्षिक प्रवेश होगा और अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त 539 बिस्तरों का अस्पताल होगा।

-संवाद ब्यूरो

बेटियों पर पूरे देश को नाज

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने प्रवास के दूसरे दिन हरियाणा राजभवन में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, महिला खिलाड़ियों व बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं से वार्तालाप की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटियों की उर्जा को आज पूरा विश्व देख रहा है। इसलिए बेटियों को हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर और आगे बढ़ना है। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान के तहत हरियाणा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेटियों को बचाने के लिए किए गए प्रयासों से लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा में लिंगानुपात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों और पात्र खिलाड़ियों के लिए अलग से तीन प्रतिशत कोटा देने का निर्णय लिया है।

हरियाणा तालाब प्राधिकरण द्वारा पूरे राज्य में करीब 19,000 तालाबों की मैपिंग की गई है। तालाब का कायाकल्प पानी के भंडारण के साथ पुनर्भरण की काफी संभावनाएं भी प्रस्तुत करता है।

लोकसंस्कृति का मह

हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 532 टीजीटी अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को रिकॉर्ड समय में स्कूल आवंटित कर स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा निशक्तजनों को शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्हें शिक्षित कर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है।

...कुंभ गीता महोत्सव

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2022 ने राष्ट्र ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना ली है। ब्रह्मसरोवर तट पर 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक चले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2022 का विधिवत समापन हुआ। महोत्सव में आए शिल्पकार अगले साल फिर से आने का वायदा करके गए। इस उत्सव में देश व प्रदेश के कोने-कोने से सांस्कृतिक कलाकारों व शिल्पकारों ने भाग लिया। महोत्सव को प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यहां कला, संस्कृति, संस्कार और अध्यात्म का संगम देखने को मिला। महोत्सव में देश-विदेश के लाखों पर्यटकों व श्रद्धालुओं ने शिरकत की। देश-विदेश के लोग महोत्सव की वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ जुड़े रहे। महोत्सव की शुरुआत से समापन तक सोशल साईटस पर विजिट करने वाले लोगों का आंकड़ा एक करोड़ से भी अधिक रहा।

तीर्थों का विकास और देखभाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महोत्सव में आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में 'तीर्थ मित्र पोर्टल' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हमें अपने तीर्थों के विकास और देखभाल के लिए आगे आना चाहिए। गांव हो या शहर जिन भी स्थानों पर तीर्थ स्थान स्थापित हैं, वहां पर स्थानीय लोगों की समिति बनानी चाहिए और तीर्थों के विकास की योजना तैयार करनी चाहिए। गीता जयंती 5159 वर्ष पूरे होने पर गीता जन्म स्थली की पावन धरा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया। इसके साथ ही हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण आहुति डाली।

कलाकारों ने दिखाए कला के रंग

महोत्सव-2022 में नेपाल, यूगांडा, अफ्रीका सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों कलाकारों ने 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक मुख्य मंच, हरियाणा पैवेलियन, सांस्कृति संध्या, ब्रहमसरोवर के घाटों पर रोजाना सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत कर पर्यटकों का मनोरंजन किया। इसके अलावा 48 कोस के 75 तीर्थों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों व जिलास्तरीय कार्यक्रमों में भी अपनी प्रस्तुति दी है। इस महोत्सव में जहां आरती स्थल पर संध्या के समय विभिन्न नामी कलाकार अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं इसके साथ-साथ मुख्य पांडाल में सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रसिद्ध सूफी गायक वडाली ब्रदर्स, कुमार विशु, गजेंद्र फौगाट, साध्वी पुर्णिमा, महावीर गुड्डू आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

प्रदर्शनी से योजनाओं की जानकारी

महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के तट पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में राज्य प्रदर्शनी में श्रीमद्भगवद्गीता के प्रसंग, गीता सार, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश, स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के वीरों के योगदान को 23 पैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार के आठ साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को दिखाया गया।

खादी ग्रामोद्योग ग्रामीणों को बना रहा उद्यमी

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी परिधानों को प्रदर्शित किया और पर्यटकों ने स्वदेशी उत्पादों को ख़ासा पसंद किया। मेले में दिल्ली और मेरठ के कारीगरों के बने हुए कुर्ते और जैकेट प्रदर्शित किए गए। स्टाल के संचालक समीर ने बताया कि वह दिल्ली से आए हैं और यह उनका पुश्तैनी कार्य है। वे 30 वर्ष के हैं और पूरे भारत में जहां पर भी अंतरराष्ट्रीय मेले लगते हैं, वो वहां जाते हैं और खादी से बने कपड़े ग्राहकों को बेचते है।

2023 में आस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। अब महाभारत स्थली कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं नजर आएंगी। कर्मयोगी धरा पर गीता महोत्सव की तर्ज पर कृष्णा उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव को मनाने के लिए शहर सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता महोत्सव का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। आगामी 2023 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर गीता गूंज सुनाई देगी। इससे पहले मारिशस, लंदन व कनाडा में गीता महोत्सव मनाया जा चुका है। कनाडा में बाकायदा गीता के नाम से पार्क स्थापित किया गया है।

राज्य पुलिस टीमों द्वारा दिसंबर माह में 7.951 किलो गांजा, 167.77 ग्राम हेरोइन, 402 ग्राम सुल्फा, 3.992 किलो अफीम, 5.350 किलो चूरा पोस्त, 242 बोतल प्रतिबंधित सीरप और इंजेक्शन बरामद किये गए।

हरियाणा सरकार प्रदेश में समान विकास करवा रही है और इसी कड़ी में उकलाना हलके के 6 सड़कों का 18 फीट चौड़ाकरण व सुदृढ़ीकरण तथा 2 सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने को मंजूरी दी गई है।

जितेन्द्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड

संगीता शर्मा

पशुपालन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह राज्य के कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 43 प्रतिशत योगदान देता है। साथ ही यह लाखों लोगों को सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त पशुपालन, डेयरी गतिविधियों विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों व महिलाओं के लिए आय के महत्वपूर्ण स्त्रोत की भूमिका निभाता है। इसी मकसद से हरियाणा का पशुपालन एवं डेयरी विभाग पशुपालकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। राज्य में स्वदेशी नस्ल की गायों की दूध रिकार्डिंग, कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, गायों को मुफ़्त उपचार एवं मुंह खुर, एच.एस., एल.एस.डी. आदि बीमारियों से बचाव के लिए रोग निरोधी टीकाकरण द्वारा साहीवाल नस्ल की गाय के डेयरी फार्म को भूरपूर सहयोग दिया जा रहा है। इन प्रयासों की बदौलत ही फतेहाबाद के गांव गिल्ला खेड़ा के जितेन्द्र सिंह को देसी नस्ल की गाय/भैंस पालन की सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में पूरे देश में प्रथम पुरस्कार 'राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, 2022' से नवाज़ा गया है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा गौजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

यह पुरस्कार 26 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह, 2022 के दौरान डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, जी.के.वी.के. परिसर बेंगलुरू, कर्नाटक में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार के सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

जितेन्द्र सिंह प्रगतिशील स्वदेशी मवेशी पालने वाले किसानों/ब्रीडरों में से एक हैं। साहीवाल गाय की नस्ल के संरक्षण, उन्नयन और प्रसार हेतु उनके पास 50 दुधारू साहीवाल गायों का स्वदेशी मवेशी डेयरी फार्म है, जिनका न्यूनतम 3,000 किलोग्राम दूध का मानक लेक्टेशन है। उन्होंने अपने फार्म में अच्छी मवेशी प्रबंधन तकनीकों के साथ-साथ कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई.), भ्रूण स्थानांतरण प्रोद्योगिकी (ई.टी.टी.) और इन-विट्रो फर्टिलाईजेशन (आई.वी.एफ.) जैसी वैज्ञानिक प्रजनन तकनीकों को अपनाया है। जितेन्द्र सिंह के साहीवाल फार्म का भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी (ई.टी.टी.) के लिए एन.डी.डी.बी. और उच्च वंशावली के साहीवाल बैल के सैक्सड सोर्टिड सीमन से जनित भ्रूण के लिए आई.वी.एफ. तकनीक के लिए जे.के. बोवाजेनिक्स, जे.के. ट्रस्ट, जीनस ब्रीडिंग इंडिया प्राइवेट.लिमिटेड. से समझौता किया है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से पशुपालकों को अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं और नई तकनीक का प्रयोग करके गाय की नस्लों को सुधारा जा रहा है।

पशुपालन को बढ़ावा देती योजनाएं

» राजकीय और केंद्रीय योजनाओं और 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' जैसे कार्यक्रमों ने स्वदेशी नस्ल के मवेशियों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य में उनकी संख्या में सुधार हुआ है।
» राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देसी गायों की नस्लों के संरक्षण एवं विकास के लिए राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई।
» गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन हेतु एक सशक्त कानून ''हरियाणा गौ-वंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम-2015'', 19 नवंबर, 2015 को राज्य में लागू किया गया।
» राज्य में हरयाना और साहीवाल जैसी स्वदेशी नस्लें काफ़ी मज़बूत हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती हैं।
» राज्य में 2,856 पशु संस्थाओं द्वारा 71.26 लाख पशुओं को पशुचिकित्सा व पशु प्रजनन संबंधित सेवाएं प्रदान करने का एक मज़बूत बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है।
» हरियाणा पशु पंजीकरण, प्रमाणन और प्रजनन अधिनियम, 2019 में पशु प्रजनन गतिविधियों को विनियमित करके पशुओं के कल्याण और आनुवंशिक सुधार के लिए कानून बनाया गया है । ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।
» राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का तीसरा चरण राज्य के पांच जिलों में शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम में 1.25 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये जा चुके हैं।
» प्रदेश में आवारा/बेसहारा पशुओं की तादात को नियंत्रित करने व पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य के पशुपालकों को कम से कम 85 प्रतिशत मादा बछड़ियां प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सैक्सड सोर्टिड सीमन का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सैक्सड सोर्टिड सीमन 200 रु. प्रति डोज की रियायती दर पर पशुपालकों को उपलब्ध करवाता है, जो पूरे देश में सबसे कम है।
» राज्य में गायों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सभी पशु संस्थाओं में 1.79 लाख डोजिज सैक्स सोर्टिड सीमन की आपूर्ति की गई है।
» राज्य में डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को 20 व 50 दुधारू पशुओं की इकाई की खरीद के लिये गये बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4 तथा 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाईयां स्थापित करने पर लाभार्थी को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

रबी फसलों का 31 दिसंबर तक करवायें बीमा

आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिला के प्रत्येक खंड के सभी गांवों में किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए जागरूक करेगी। प्रचार वैन के साथ बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि तथा कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी साथ रहेंगे ताकि किसानों की शंकाओं का मौके पर समाधान किया जा सके। सरकार द्वारा खेती को जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सीजन रबी-2022-23 के अंतर्गत गेंहू, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसल का 31 दिसंबर 2022 तक बीमा करवाया जा सकता है। योजना के तहत स्थानीय आपदा, फसल बुआई से कटाई तथा कटाई के बाद के नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। किसान को गेंहू की फसल का बीमा करवाने के लिए 429.98 रुपए प्रति एकड़, जौ की फसल के लिए 281.14 रुपए प्रति एकड़, चना फसल के लिए 214.99 रुपए प्रति एकड़, सरसों फसल के लिए 289.41 रुपए प्रति एकड़ तथा सूरजमूखी फसल के लिए 281.14 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। किसानों को आह्वान किया जाता है कि वे 31 दिसंबर 2022 तक अपनी रबी की फसलों का बीमा अवश्य करवायें।

यह योजना ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। गैर ऋणी किसान नजदीकी अटल सेवा केंद्र से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। फसल बीमा करवाने के लिए किसान आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, भूमि एवं फसल बुआई से संबंधित दस्तावेज साथ लेकर जाये। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नम्बर 1800-180-2117 पर सम्पर्क कर सकते है।

-संवाद ब्यूरो

फार्ममित्र ऐप पर कृषि संबंधित सेवाएं उपलब्ध :-

कृषि संबंधित सेवाएं अब फार्ममित्र ऐप पर उपलब्ध है। इनके तहत दावे के भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, मौसम पूर्वानुमान, बाजार भाव, बीमा सेवा व अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वैकल्पिक उर्वरकों का भी प्रयोग करें किसान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को गेंहू की बिजाई के लिए पर्याप्त डीएपी खाद उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। किसान गेंहू की बिजाई में डीएपी खाद के स्थान पर एसएसपी व एनपीके का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 23 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 52 हजार मीट्रिक टन एसएसपी एवं 7 हजार मीट्रिक टन एनपीके स्टॉक के रूप में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीएपी खाद के स्थान पर गेंहू की बिजाई में दूसरे उर्वरक भी प्रयोग किये जा सकते हैं।

हिसार स्थित चौ. चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की सिफ़ारिश के अनुसार एक बैग डीएपी या 3 बैग एसएसपी या डेढ़ बैग एनपीके का प्रयोग करके फास्फोरस की आपूर्ति पूर्ण कर सकते हैं। गत वर्ष सितंबर से नवंबर माह तक प्रदेश में 2 लाख 78 हजार मीट्रिक टन डीएपी बिक्री हुई थी, जबकि इस वर्ष सितंबर से नवंबर माह (21 नवंबर तक) प्रदेश में 3 लाख 6 हजार मीट्रिक टन डीएपी की बिक्री हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में प्रतिदिन 2 से 3 हजार मीट्रिक टन डीएपी/एनपीके उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा खाद की बिक्री प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से की जानी सुनिश्चित की है। किसान संयम रखते हुए शांति पूर्वक खाद की खरीद करें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले।

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर, 2022 से शुरू होगा। इस संबंध में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दतात्रेय ने अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य में 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना' के तहत वृद्धजनों को 2,500 रुपए प्रतिमाह की दर से लाभ दिया जा रहा है, जो देशभर में सर्वाधिक है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए पुराने वाहनों पर लगेगी ब्रेक

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जहां एक ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैप नीति बनाने के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई, वहीं कपड़ा उद्योग को मज़बूत करने की दिशा में 'नई हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल नीति 2022-25' को स्वीकृति प्रदान की गई है।

हरियाणा वाहन स्क्रैप नीति के तहत दस वर्ष की अवधि पूरी कर चुके डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष की अवधि पूरी चुके पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप किया जा सकेगा। यह नीति पांच साल की अवधि के लिए तैयार की गई है। यह नीति अवधि समाप्त कर चुके सभी वाहनों, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं, पंजीकरण प्राधिकरणों और विभागों पर लागू होगी, जिन्होंने आरवीएसएफ के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना है।

नीति के तहत, वसूले जाने वाले मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत तक या जमा प्रमाणपत्र में उल्लिखित स्क्रैप मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, छूट देने का प्रावधान होगा। जमा प्रमाणपत्र के आधार पर खरीदे गए नए वाहन के पंजीकरण पर पंजीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।

आत्मनिर्भर टैक्सटाइल नीति

कपड़ा क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए नई हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल नीति 2022-25 को मंजूरी दी गई है। नीति का उद्देश्य बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए एक मज़बूत प्रोत्साहन ढांचे की पेशकश करके मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में वृद्धि, परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, कढ़ाई, बुनाई, प्रसंस्करण, रेडीमेड में निवेश को आकर्षित करके आत्मनिर्भरता और नवाचार के एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, नीति में गारमेंट्स, अपैरल मेकिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इंटीग्रेटेड यूनिट्स, टैक्सटाइल पार्क्स, टैक्सटाइल क्लस्टर्स आदि में वैल्यू एडिशन, रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति से टैक्सटाइल क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित होगा तथा समस्त मूल्य श्रृंखला में टैक्सटाइल क्षेत्र में 20,000 नए रोज़गार सृजित होने का अनुमान है।

विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम

हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए, अन्य संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधानों के अलावा अपेक्षित प्रपत्रों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रक्रियात्मक प्रावधान प्रदान करने के अभाव में अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हरियाणा विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियमावली, 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।

भूमि पार्टनरशिप नीति

लैंड पूलिंग परियोजना के मामले में उन भूस्वामियों को जिन्हें तत्काल नकदी की आवश्यकता है और वे अपने हिस्से का इंतजार नहीं कर सकते ऐसे भूस्वामियों के लिए हरियाणा लैंड पार्टनरशिप नीति -2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। भूमि एकत्रीकरण के लिए राज्य सरकार की ई-भूमि और लैंड पूलिंग नीति पहले से ही बेहतर कार्य रही हैं, फिर भी हरियाणा लैंड पार्टनरशिप नीति - 2022 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

205 आयुष चिकित्सकों की भर्ती

हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयुष चिकित्सकों के 205 पद भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। निर्णय के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 175 पद, रेजिडेंट फिजिशियन, यूनानी चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक के चार पद, यूनानी चिकित्सा अधिकारी के आठ पद और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 18 पद भरे जाएंगे।

इन्हें भी दी गई मंजूरी

- रेवाड़ी जिले के माजरा मुस्तिल भाल्खी में एम्स की स्थापना के लिए 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि एक रुपए प्रतिवर्ष प्रति एकड़ की दर से 99 वर्षों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लीज पर देने के प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड के माध्यम राज्य भर में चौबीसों घंटे प्रभावी संचालन और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत विधानसभा सदस्यों द्वारा अधिसूचित सचिवालय भत्ता और चालक भत्ता सीधे किसी व्यक्ति के खाते से डेबिट किया जाएगा।
- हरियाणा के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित नगर नियोजन योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं और नगर सुधार ट्रस्ट योजनाओं में भूखंडों के अवैध सब-डिविजन/ भूखंडों के नए सब-डिविजन के नियमितीकरण के लिए नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
- 'सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली नियम, 2022' को अंतिम रूप देने के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

-संवाद ब्यूरो

मैं शपथ लेता हूं कि ..

पंच, सरपंच, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण

पंचायती राज संस्थाओं में भी लोकसभा व विधानसभा की तरह एक या दो दिन का सेशन हो ताकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं पर गौर कर सकें तथा बेहतर प्रस्ताव पास कर विकास किया जा सके। सभी जन प्रतिनिधि पांच वर्ष तक बिना भेदभाव के अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य करें। पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानें और सेवा के भाव से दायित्व निभाते हुए क्षेत्र का विकास करें। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने इन्हें शपथ दिलाई। यह पहला अवसर रहा जब पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय स्तर पर 'मैं शपथ लेता हूं कि..' कहने का गौरव हासिल किया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को बधाई दी और पंचायत को गांव की सरकार बताया। प्रदेशभर के हर जिले, ब्लॉक व गांव में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 6200 सरपंच, 60,133 पंच, 3081 ब्लॉक समिति सदस्यों व 411 जिला परिषद सदस्यों ने शपथ ली।

60 प्रतिशत जनप्रतिनिधि चुने सर्वसम्मति से

पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों की कुल 71,696 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इनके लिए 1,60,192 ने नामांकन किया, 2600 के नामांकन रद्द हुए और 31,900 ने नामांकन वापिस ले लिया। 40,500 जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए, जो करीब 60 प्रतिशत हैं। वहीं 29,474 सीटों के लिए 85,127 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11 लाख रुपए, सरपंच को 5 लाख रुपए, पंच चुने जाने पर 50 हजार रुपए और ब्लॉक समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के सर्वसम्मति से चुने जाने पर 2-2 लाख रुपए दे रही है। इस तरह चुने जाने पर हरियाणा सरकार 300 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए दे रही है।

-संवाद ब्यूरो

अच्छी तरह जिम्मेदारी निभाएंगे पंचायत प्रतिनिधि

हमारी शिक्षित व सक्षम पंचायती राज संस्थाएं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करते हुए सशक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। गांव के विकास को बिजली, पानी व सड़क तक सीमित न रख के गांव के चहुमुंखी विकास को आगे बढ़ाएंगे। सभी प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में छोटी सरकार के रूप में बेहतर काम करेंगे।

-देवेंद्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री

ग्रामीण विकास के लिए हरियाणा सरकार वचनबद्ध

ग्रामीण विकास के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्य चुनी गई पंचायतों के माध्यम से ही गांवों तक पहुंचते हैं। हरियाणा सरकार ने 2015 में पंचायती राज अधिनियम में संसोधन करके पढ़ी-लिखी पंचायत बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया तथा पिछड़ा वर्ग-ए को भी आरक्षण दिया। स्टाम्प ड्यूटी का दो प्रतिशत व बिजली बिल में लगने वाले दो प्रतिशत सैस का हिस्सा पंचायतों को दिया जा रहा है। ग्राम सचिवालय कुछ जगह बन गए हैं अन्य की प्रक्रिया जारी है। जिला परिषद कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालयों का काम भी पूरा किया जाएगा। गांवों में युवाओं व एनजीओ आदि की समिति बनाई जाए, ताकि वह गांव में सुधार करे और भ्रष्टाचार आदि पर निगरानी रखे।

-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

पीएम नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में चले गीता महोत्सव के बारे में फीडबैक ली है। सांसद नायाब सिंह सैनी की ओर से प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि महोत्सव का अवलोकन करने के लिए देश विदेश से लगभग 40 से 45 लाख लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे।

समाज सेवा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए ही हरियाणा सरकार ने Samarpan.haryana.gov.in पोर्टल बनाया है, जिस पर व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत कर सामाजिक कार्यों में सरकार का सहयोग कर सकते हैं।

आजादी के अमृत महोत्सव में दास्तान-ए-अंबाला

अम्बाला छावनी सुभाष पार्क के ओपन एयर थियेटर में 'दास्तान-ए-अम्बाला' का मंचन हुआ। नाटक के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय करते हुए इसे जीवंत किया जिसमें 1857 में क्रांति की ज्वाला अम्बाला छावनी से कैसे फूटी को पूरी तरह से दर्शाया गया। नाटक को समूचे हरियाणा में प्रदर्शित किए जाने की मांग हुई ताकि लोग जान सकें कि 1857 की क्रांति अम्बाला से कैसे प्रारंभ हुई।

अम्बाला की दास्तान नाटक में दिखाया गया कि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का जन्म अम्बाला छावनी से हुआ और आजादी की ज्वाला अम्बाला छावनी से उठी। सभी ने बेहतरीन तरीके से इसमें अभिनय किया और सारे अम्बाला की उस समय क्या-क्या भूमिका रही और कैसे अम्बाला से आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से 9 घंटे पहले अम्बाला छावनी स्थित 60वीं नेटिव इन्फेंटरी से शुरू हुई इसका वर्णन किया गया। अम्बाला छावनी में आज भी काली प्लाटून का पुल है और उस पुल के पार ही नेटिव इन्फेंटरी यूनिट थी और पुल के दूसरी ओर यूरोपियन लाइन थी। नेटिव इन्फेंटरी ने 10 मई को प्रातः 9 बजे हथियार लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और 12 बजे 5वीं नेटिव इन्फेंटरी ने युद्ध का ऐलान किया। रविवार के दिन सभी अंग्रेज चर्च में जाते थे और योजना यह बनी थी कि सभी अंग्रेज चर्च में एकत्रित होंगे तो सभी को मारकर दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। मगर, एक सिपाही श्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों को योजना पहले बता देने से अंग्रेज अलर्ट हो गए। मगर, जिस समय हथियार लेकर भारतीय सिपाही बैरकों से निकले तो आंदोलन आरंभ हुआ और इसके बाद हरियाणा के अन्य शहरों के अलावा मेरठ व देश के अन्य हिस्सों में जंग लड़ी गई।

बताते हैं 1857 में आजादी की लड़ाई की पूरी प्लानिंग की गई थी और इतिहासकार मानते हैं कि इसकी प्लानिंग अम्बाला छावनी से की गई थी, वैसे तो 26 मार्च से जो इस क्रांति में बाधा थे उन सबके घरों व दफ्तरों को क्रांतिकारियों ने आग के हवाले करना आरंभ कर दिया था।

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला की भूमि पवित्र भूमि है और यहीं से देश को आजाद कराने के लिए ज्वाला भभकी, इसके बाद ही देश को आजादी मिली और आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं।

शहीदों को समर्पित बन रहा शहीद स्मारक

गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक जीटी रोड पर बनाया जा रहा है जिस पर 400 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। स्मारक में अलग-अलग माध्यमों से जंगे-ए-आजादी को दिखाया जाएगा। पहले हिस्से में अम्बाला छावनी में क्रांति की ज्वाला, दूसरे हिस्से में हरियाणा और तीसरे हिस्से में समूचे देश में 1857 की क्रांति को भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया जाएगा। हमें यही पढ़ाया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, मगर कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था जबकि उससे 28 साल पहले 1857 में लोगों ने लड़ाई लड़ी, मगर उन्हें कभी याद नहीं किया गया।

विज ने कहा कि यह सब जानने के लिए हिंदुस्तान के 6 प्रमुख इतिहासकारों की समिति बनाई जिसमें अम्बाला के 2 इतिहासकारों को जिनमें प्रो. यूवी सिंह व तेजिंद्र सिंह वालिया को शामिल किया गया है जोकि एक-एक तथ्य को निकाल शहीद स्मारक में प्रदर्शित करेंगे। 1857 की क्रांति में रोटी और कमल के फूल का महत्व था और शहीद स्मारक में 70 फुट ऊंचा कमल का फूल बनाया जाएगा। शहीद स्मारक में 85 प्रतिशत सिविल वर्क पूरा हो चुका है जबकि आर्ट वर्क के जल्द टेंडर होंगे। हिंदुस्तान के बड़े म्यूजियम बनाने वाली कंपनियों द्वारा शहीद स्मारक में कार्य करने की उम्मीद है।

अनिल विज ने बताया कि वे 20 साल से शहीद स्मारक निर्माण के लिए लड़ते आ रहे थे। उनकी सरकार के आते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत इसे अम्बाला छावनी में बनाने की मंजूरी दी जो हम सबके लिए गौरव की बात है।

-संवाद ब्यूरो

सुण छबीले बोल रसीले

दो नंबर की कमाई, कदे काम ना आई

छबीला अख़बार पढ़ रहा था तो रसीला आकर पूछता है- सुणा प्यारे, के सै आज की ताजा ख़बर?

छबीला कहता है- यार एक बात कोनी समझ में आती। जिब अधिकारी और कर्मचारियां नै इस बात का इलम सै अक इस राज में रिश्वत का पैसा लेणा और देणा जुर्म सैं, तो क्यूं नहीं टिकते। कोय ना कोय हत्थे चढ़्या पावै सै।

- भाई छबीले, कुछेक अधिकारी और कर्मचारियां की आदत खराब सै। आदत तो छुटती-छुटती छुटैगी। पहल्यां की बिगड़ी होई नीयत इतणी आसानी तैं कोनी सुधरै, टैम लागैगा। कुछेक तो इसे माणस भी सैं अक उनकी आदत उलझे पाछै भी कोन्या छूटती।

- रसीले जिब सरकार नै सख्त निर्देश दे राखे सैं अक भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरियां जीरो टोलरेंस की नीति अपणाई जावैगी तो इन मुलाजिमां नै समझणी चाहिए।

- छबीले, बहुत से मुलाजिम जिनकी आदत खराब थी वे ईब कोई रिश्वत ना लेते, पर नीयत में फेर भी डांगर हांडते नजर आवैं सैं। इस नीयत के चालते वे कुछ कर तो सकते नहीं, भड़भड़ाण लागज या सैं।

- मैं तो एक बात जाणूं सूं रसीले, इतिहास ठाकै देखल्यो। दो नंबर की कमाई, किसे कै काम नहीं आई। उसका नुकसान होया, किसे कै गेल्यां-गेल्यां होग्या, किसे कै दो दिन पाछै होग्या। कुल मिलाकै जो कमाई करी थी उसका हिसाब आड़ैए बराबर होज्या सै।

- हां भाई, दो नंबर की कमाई करण आले माणस नै कदे सुख की नींद तो आवै कोन्या। सारी हाणा भीतर आले में डर बैठा रहैगा। इस डर में वो या तो दारू पीवैगा या नींद की गोली खावैगा। तावली ए फेर उसकी यात्रा पूरी होज्या सै। तो फेर इसा सोना किस काम का जो कानां नै काटै।

- रसीले, जिब तैं इस सरकार नै सुशासन की व्यवस्था बणाई सै, बहुत से गोरखधंधे बंद होगे। सरकारी दफ्तरां तैं दलाल इसे भाजगे जिसे गधे के सिर तैं सींग।

- हां भाई जै यो सरकार कुछेक साल और ना आती तो दलाल भी सरकार तैं मान्यता प्राप्त होज्याते और रिश्वत का लेण-देण कानूनी रूप धारण कर लेता।

-इसमें कोई दो राय कोन्या। सरकारी महकमां में नौकरी और तबादलां के रेट फिक्स होगे थे। इतणा ए नहीं मंत्री संतरियां के कोटे भी फिक्स थे। वे चाहे रेगूलर नौकरी के हों या ठेके की नौकरी के। और तो और कार्यकर्ताओं के कोटे भी फिक्स थे। न्यू कहा जाया करता अक रैली में जो जितणे ट्रैक्टर- ट्राली भरकै ल्यावैगा उसके उतणे ए बालक नौकरी लाए जावैंगे। इसके लिए बाकायदा रैली स्थल के बाहर विडियो फिल्म बणाई जाया करती।

- हां रसीले, इनै वजहां तैं लोग मंत्री-सतंरियां के पाछै-पाछै लागे रहा करते। सड़कां पै गाड़ियां का पूरा लांबा काफिला चाल्या करता। आम आदमी उनकी भीड़ तैं परेशान था।

- और सुण छबीले, कोई ब्याह शादी में जै किसे नै गलती तैं किसे मंत्री-संतरी का न्यौता दे दिया तो जीमणियां की पूरी फौज आया करती। कन्यादान सौ रुपए और खा जाते हजार का। ईब वो सीन कोन्या दिखाई देता। किसै जन प्रतिनिधि के पाछै ना तो कार्यकर्ता होते और ना काम कराण आले लोगां का जमावड़ा दिखाई देता।

- भाई ईब सबनै बेरा लागग्या अक जो सरकारी काम होणे सैं वे ऑनलाइन होणे सैं, और काबिलियत के आधार पै होणे सैं। और तो और ठेके भी ईब ऑनलाइन होगे। तो किसे के आगै-पाछै हांडण की जरुरत के रहैगी?

- सबकुछ पारदर्शी।

- छबीले, बोहत से माणस तो ईब न्यू भी परेशान सैं अक इस घपड़चौथ पै प्रतिबंध क्यूं लागग्या। आच्छा नलका सा लागर्‌या था।

- हां भाई इसे माणस भी सैं। पर इसे कम सैं। वरना ज्यादातर जनता शांति तैं और अनुशासन में ए रहणा चाहवै सै।

- एक और हैरानी की बात। जो माणस इस तरियां के साफ सुथरे सिस्टम नै देखकै परेशान सैं, वे ही लोग दूसरे देशां के उदाहरण दे कै न्यू कहैं सैं अक फलाणे देश में सुरग सै। उड़ै न्यू, उड़ै न्यू। आपणे कान्यां कोन्या देखैं, आपणी नीयत कितणी ठीक सै? दूसरे में कमी काढण की कोशिश करैंगे।

- हां भाई जीण का असली मजा तो जिबै सै जिब आपणा आपा बढ़िया हो। एक दूसरे का सहयोग करैं। गलत कामां तैं दूर रहैं। आपणे आसपास सफाई का ध्यान राखैं। रिश्वत ना लेवै और ना देवै। बख्त की गेल्यां चालते हुए काम करैं, मेहनत करैं। छोटे बड़्यां का मान सम्मान करैं। देख फेर क्यूकर ना सुख की नींद आवै। सुख की नींद आवैगी तो सेहत भी ठीक रहैगी। सेहत ठीक रहैगी तो डाक्टर धौरै नहीं जाणा पड़ैगा। कोई लालच या झगड़ा नहीं करैगा तो थाने कचहरी जाण की भी जरुरत नहीं पड़ैगी।

- इन धौरै नहीं जाणा होगा तो घर में आपै खुशहाली आवैगी। गाम-गुहांड में दो नमस्ते फालतू मिलैंगी।

- छबीले ये सारे गुण जिबै आवैं सैं जिब गीता या गीता जैसी किताबां का अध्ययन कर्‌या जा।

- इसी बात नहीं सै, रसीले, जीवन में मेहनत, ईमानदारी और नेक विचार हों तो सबकुछ बढ़िया ए बढ़िया हो सै। जो घणी धन माया की कोळी भरण की कोशिश करैगा वो दुखी रहैगा। इसलिए त्याग और तपस्या का संतुलन जरुरी सै।

- मनोज प्रभाकर

सूरज को नहीं डूबने दूंगा

अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा
देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिये हैं
मुट्ठियाँ मजबूत कर ली हैं
और ढलान पर एड़ियाँ जमाकर
खड़ा होना मैंने सीख लिया है
घबराओ मत
मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ
सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढकने लगेगा
मैं कंधे अड़ा दूंगा
देखना वह वहीं ठहरा होगा
अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा
मैंने सुना है उसके रथ मे तुम हो
तुम्हे मैं उतार लाना चाहता हूं
तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो
तुम जो साहस की मुर्ति हो
तुम जो धरती का सुख हो
तुम जो कालातीत प्यार हो
तुम जो मेरी धमनी का प्रवाह हो
तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो
तुम्हे मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूं
रथ के घोड़े
आग उगलते रहें
अब पहिये टस से मस नहीं होंगे
मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिये हैं।
कौन रोकेगा तुम्हें
मैंने धरती बड़ी कर ली है
अन्न की सुनहरी बालियों से
मै तुम्हे सजाऊँगा
मैंने सीना खोल लिया है
प्यार के गीतों में मैं तुम्हे गाऊंगा
मैंने दृष्टि बड़ी कर ली है
हर आखों में तुम्हे सपनों सा फहराऊंगा
सूरज जायेगा भी तो कहाँ
उसे यहीं रहना होगा
यहीं हमारी सांसों में
हमारी रगों में
हमारे संकल्पों में
हमारे रतज़गों में
तुम उदास मत होओ
अब मैं किसी भी सूरज को
नहीं डूबने दूंगा

- सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com